[श्री मूल चन्द डागा]

सभापति जी, कमेटी ने रेकमेंडेशन किया वह अलग और आप का बिल अलग, तो अब बतलाइए कि हम इस को मानें या न मानें ? आप कहेंगे कि यह तुम कैसे कहते हो ? तो हम चुप हैं। आप बिल पढ़िये। कौन वाइसचांसलर होगा ? पार्लियामेंट में सब से पहले डिस्कशन यह होना है कि वाइसचांसलर कौन होना चाहिए। इस में दिया है

The Visitor shall appoint the Vice-Chancellor What will be the qualifications? It will be decided later on

(व्यवधान) मैंने कहा एक का तो सवाल ही नहीं है। क्वालीफिकेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है।

अब एक एक क्वेश्चन लीजिए। एक तरफ तो आप जो ये हिन्दुस्तान के भाग्य विधाता हैं उनके सेलेक्शन की बात देखिए उन का सेलेक्शन कैसे होगा ? कौन टीचर्स लिए जायेंगे ? हिन्दुस्तान के जिस आदमी को कहीं नौकरी नहीं मिलती वह टीचर बन कर आता है और वह फिर सीधे पार्लियामेंट में आना चाहता है। पार्लियामेंट में नहीं आए तो विदेश जाना चाहता है फारेन कन्ट्रीज के टूर के लिए। जितने कालेजेज के प्रोफेसर्स बनते हैं वह यह समझते हैं कि किसी न किसी तिकड़म से कहीं न कहीं आगे जावें। चाहे कहीं वाइसचांसलर बनें या इंग्लैंड चले जावें या कहीं मीटिंग में मेम्बर बनें। ट्यूटोरियल या बच्चों को पढ़ाने का तो सवाल ही नहीं है। तो दो चीजें इम्पार्टेंट हैं एक टीचर एक वाइसचांसलर, दोनों के लिए इसमें कुछ नहीं है और अब अगर हम कहते हैं कि आप ने ऐसा क्या किया तो आप कहेंगे कि कोई जरूरी नहीं है, हम हरीडली पास कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने कह दिया और लोग कहते हैं कि जल्दी करें, मैं अपना प्रस्ताव विदड्रा करूं। क्यों करूं क्योंकि जुलाई में स्थापना करनी है। तो करिए। जुलाई दो महीने है, तो दो महीने के अन्दर करिए।. . (व्यवधान) .. ..

अब मैं खास खास प्वाइंट्स ले रहा हूं।

सभापति महोदय : आप ने घंटी सुनी या नहीं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने तो ज्वाइंट कमेटी में भेजने का मोशन दिया था। इसलिए मैंने आप से प्रार्थना की . . . .

सभापति महोदय : इसीलिए आप को ज्यादा टाइम दिया गया।

श्री मूल चंद डागा : अब मैं आपका आबजेक्ट बता रहा हूं कि आप ने क्या आब्जेक्ट लिया। सवाल यह पैदा होता है कि जितना पैसा हम खर्च करने जा रहे हैं, उस में लोगों के शारीरिक विकास की भी कोई व्यवस्था है या नहीं है। जिन बच्चों को आप पढ़ायेंगे, उनके शारीरिक विकास के लिए, फिजिकल डवेलपमेन्ट के लिए कहां प्रावीजन किया है—यह आप का क्लाज 4 है, मुझे तो इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है।

एक बहुत बड़ी बात आप ने इस में कही है—

> "Any authority of the University may appoint as many Standing or Sub-committees as it may deem fit".

Which is that authority?

सभापति महोदय : आप अपनी तकरीर कल जारी रखें।

17.33 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

Completion of Western Kosi, Rajasthan and Gandak Canal Projects

सभापति महोदय : अब हम आधा घन्टे की बहस ले रहे हैं। इसमें कुछ वक्त मूवर साहब लेंगे, कुछ मिनिस्टर साहब लेंगे। इनके अलावा कुछ सवालात भी पूछे जायेंगे। एक चिट्ठी भी इस सिलसिले में आई थी, लेकिन वक्त पर नहीं आई, इस लिए उनको इन्क्लूड नहीं किया

गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको भी कुछ टाइम प्रश्न पूछने के लिए दिया जाय।

We divide like this: 10 to 12 minutes for the Mover; then sometime for questions; and then 10 minutes for the Minister to reply.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर): सभापति जी, अन्नोत्पादन के वृद्धि की बातो को सुनने के बाद यह देश एक बार फिर अन्न सकट के कगार पर खड़ा है, खाद्यान्न महगे हो रहे है, विदेशो से बड़े पैमाने पर मगाने की शर्मनाक तरीके से बातें हो रही है। यद्यपि प्रधान मत्री जी ने इस का खण्डन किया है कि 70 लाख टन अनाज मगाने की बात सही नही है लेकिन खाद्य मत्रालय जिस तरह से मुनाफाखोरो को सरक्षण देने की नीति पर चल रहा है, कुछ महीने के बाद 70 लाख टन या उस का कुछ भाग मगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति मे जो हमारे यहा सिंचाई की बड़ी योजनाये है, खास कर गण्डक, कोसी, राजस्थान नहर—अगर सरकार इन्ही योजनाओ की पूर्ति कर ले तो इतने खाद्यान्न की वृद्धि जरूर हो जायेगी कि विदेशो से मगाने का खतरा खत्म हो जायेगा। लेकिन आज तक जो कुछ हम देखते आये है—यह सरकार इन योजनाओ को इस दृष्टि से नही देख रही है कि हमारी बहुत सी दिक्कतो का हल इन से हो जायेगा। बेकारी के सवाल के लिए, लोगो को काम देने के लिए, क्रैश प्रोग्राम के लिए अलग-अलग पैसे सरकार द्वारा दिये जा रहे है—हो सकता है कि इन योजनाओ मे एक करोड़ लोगो को काम मिल जायेगा, लेकिन यह समस्या का हल नही है। राज्य सरकारे जिस हद तक काम कर पाती हैं, उस हद तक आप पैसा देने के लिए तैयार है, फिर भी यदि काम तेजी से पूरा न हो तो उस का समाधान कैसे होगा। यदि राजस्थान सरकार नहर के काम को नही कर पायी है या वह अक्षम है तो फिर केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए, केन्द्र सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह स्वय उस काम को पूरा कराए। आज इन योजनाओ के पूरा न होने से देश का बड़ा अहित हो रहा है-- यह क्षेत्र सरहद का हिस्सा है, मुर्दा सरहद नहीं है, जिन्दा सरहद है, बहुत उपजाऊ भूमि है, वहां के लोग खतरों का मुकाबला करने मे सजग हैं। ऐसी स्थिति में यदि राजस्थान सरकार उस के लिए कम उत्सुक है तो भारत सरकार को सचेष्ट हो कर आगे आना चाहिए और उसे पूरा कराना चाहिए। आप इस के लिए अथारिटी बनाये और रकम दे कर, उन को अधिकार दे कर इस पाच साला योजना के अन्दर-अन्दर इन तीनो योजनाओ को पूरा करायें।

हमारे मत्री महोदय से जब प्रश्न का जवाब पूछा जाता है तो बड़ी सदिच्छा के रूप मे नीति का ऐलान कर देते हैं। लेकिन जब उन से स्पष्ट जवाब देने के लिए कहा जाता है तो उस समय उल्टा जवाब दे देते है। जिस प्रश्न पर आज की बहस शुरू हुई है, उस का उत्तर देते हुए मत्री महोदय ने कहा था—

> "Efforts should however be made to complete the Western Kosi Canal, Rajasthan Canal and Gandak canal during the Fifth Plan".

यह उन का लिखित जवाब था लेकिन जब बाद मे स्पष्टीकरण की माग की गई तो उन के जवाब मे मालूम पड़ता है कि वह उस से मुकर गये। जब उन से पूछा गया कि इस पचवर्षीय योजना मे पूरी होगी या नही तो कहने लगे कि राज्यों से जवाब आयेगा तब विचार करेगे।

सभापति जी, इन मे कुछ योजनाये तो राजनीतिक हथकण्डो के रूप मे इस्तेमाल की जा रही है। माननीय सदस्य जानते है कि पश्चिमी कोसी नहर का तीन बार उद्घाटन हुआ लेकिन कार्य अभी तक आरम्भ नही हुआ। देश मे ऐसी कोई भी दूसरी योजना नहीं है जिस का तीन बार उद्घाटन हुआ हो। एक बार श्री जगजीवन राम जी ने 1957 मे उद्घाटन किया था, जब वह रेल मत्री थे। उस के बाद 1962 में जब श्री विनोदानन्दजी मुख्य मत्री थे, मतदान से 15 दिन पहले उन्होने उद्घाटन किया और

[श्री भोगेन्द्र झा]

तीसरी बार श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उदघाटन किया . . . . . .

सभापति महोदय : उसी जगह पर ?

श्री भोगेन्द्र झा : ठीक उसी जगह पर— पश्चिमी कोसी नहर पर और यादगार के तीन स्तम्भ खड़े किये गये और आज वे तीनों स्तम्भ रो रहे है।

चौथी बार फिर उदघाटन कराने की योजना थी और सुना था कि प्रधान मंत्री जी आयेंगी, लेकिन फिर हम ने कहा कि हम विरोध करेंगे अगर वह उदघाटन के लिए आयेंगी। कहने का तात्पर्य है कि तीन बार उदघाटन हो चुका लेकिन आज तक कार्य आरम्भ नही हुआ, एक इंच जमीन भी वहा नही ली गई और खुदायी की तो कोई बात ही नही है। हर चुनाव के पहले उस का इस्तेमाल करो—ऐसी शासक दल की नीति रही है। जब भी कार्य आरम्भ करने की बात आती है—उस दिन, सभापति जी, मैंने यह सवाल उठाया था—क्या बड़े बड़े भूस्वामियों का एक तबका इस मे रुकावट डाल रहा है। मै बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं—बिहार सरकार के जो बड़े बड़े भूस्वामी है, जो मिनिस्टर भी है, हजारों एकड जमीन के मालिक है हदबन्दी कानून से बचने के लिए, चोरी करने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे है कि यह योजना पूरी ही न हो और मै जानता हूं जब तक जन-आन्दोलन उन के गले पर सवार नही होगा तब तक वे पकड मे नही आयेंगे। ऐसे लोग मिनिस्टर बने हुए है और इन लोगों ने मंत्रणा की है कि अगर यह नहर चालू हो गई तो उन की आधी जमीन हदबन्दी मे चली जायेगी, इस लिए छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के जरिये वे लोगो पर अहसान डालना चाहते है। एक बार इस गांव मे दे दिया, तो दूसरी बार दूसरे गांव मे दे दिया अगर यह योजना पूरी हो जायेगी तो अहसान डालने का मौका नही रहेगा, सब के लिए सिंचाई का प्रबन्ध हो जायेगा। उस दिन योजना मंत्री जी ने इस बात का खण्डन किया था, लेकिन महाराष्ट्र मे भी यही हुआ है। महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री जी ने भी ठीक यही काम किया है और अब तो यह मामला 'ब्लिट्ज' साप्ताहिक में भी छप चुका है। 4 अप्रैल को यह प्रश्न यहां आया था, उस के बाद उस में छपा—वहां भी ऐसा ही हुआ है।

पश्चिमी कोसी नहर के बारे मे एक बहाना यह किया जाता है कि नेपाल ने भूमि नही दी है। लेकिन अब तो नेपाल ने भी भूमि दे दी है, वहां तो खुदायी भी शुरू हो गई है, लेकिन भारत के हिस्से मे आपने कुछ नही किया है और न एक इंच जमीन अभी तक अधिग्रहण की गई है। यह बडी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

जहा तक राज्य सरकारों की मांग का सवाल है, मेरे प्रश्न के उत्तर मे सिंचाई मंत्री जी ने कहा है कि पश्चिमी कोसी नहर के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना मे 25 करोड रुपये की मांग की गई है। पूरी परियोजना 40 करोड की है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार की जो भी मांग है उसका केन्द्रीय सरकार पूरा मान ले तो फिफ्थ प्लान मे उसको पूरा करने का सवाल ही नही है सिक्स्थ प्लान मे ले जाने की बात निश्चित रूप से होगी। सौ फीसदी भी मान लिया जाये तब यह स्थिति होगी क्योंकि केवल 25 करोड की मांग की गई है। वह और रुपया मांगते है, अलग-अलग ऐसी योजनाएं है जो लागू हो तो पैसा बचेगा क्योंकि दो फिट की खुदायी हुयी और 8 फिट की नपायी हुई, ऐसे ठेकेदार वहां पर बैठे हुए है जोकि शासक दल को वोट देने वाले है लेकिन ऐसी नहर की योजना जो टिकाऊ होगी उसकी दिलचस्पी की स्थिति यह है कि 25 करोड़ की मांग की है जबकि 40 करोड से कम खर्चा नही होगा। वही राजस्थान का मामला है। इतने बड़े पैमाने पर बेकारी है, क्रैश प्रोग्राम की बात कही गई है, वर्तमान योजना मंत्री ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है लेकिन अगर राजस्थान, गण्डक, पश्चिम कोसी नहर का काम आप युद्धस्तर पर चालू कर दे तो उससे बड़े पैमाने पर उन इलाको के लिए ही नही, असल-

बगल के इलाकों में भी बेकारों को काम देने का तुरन्त और कोई साधन हो नही सकता है और भविष्य का इन्तजाम तो उससे होगा ही। फिर कैश प्रोग्राम के लिए अलग से पैसे की मांग क्यों कर रहे है। राज्य सरकारें अन्न मांगती है तो उसके लिए हमें अमरीका से धतूरा मंगाना पड रहा है। अगर फखरुद्दीन साहब इस विभाग के मन्त्री रहे तो 70 लाख टन जरूर धतूरा मंगायेंगे और प्रधान मंत्री का गलत साबित करेंगे इस बात का हमें इत्मीनान है। अन्न मंत्रालय मुनाफाखोरों को बचाने के लिए चल रहा है। मैं कीमत तय करने वाली कमेटी में था और इनके रुख को देखकर मैं यह कह रहा हू। ऐसी स्थिति में यह जो बडी योजनायें है उनको केन्द्र निश्चित रूप से पूरा करे, राज्य के जरिये कराए, खुद करे या फिर बेहतर होगा कोई स्वतन्त्र आटोनामस एथारिटी कायम कर दे लेकिन पैसा निश्चित रूप से दे, पांचवी योजना के अन्त तक निश्चित रूप से पूर्ण करने की गारन्टी करें ताकि खाद्यान्न की जो कमी है उसको पूरा करने की दिशा में देश आगे बढ सके। इस आग्रह के साथ मैं मन्त्री जी का बयान चाहता हू क्योंकि इससे हमारे देश की उन्नति का सम्बन्ध है हमारे देश की आजादी और प्रभुसत्ता का इससे सम्बन्ध है, हम जानते है भूखा मरेंगे तो धतूरे के लिए अमरीका दौडना पडेगा और जो हमारी प्रभुसत्ता पर अमरीका से चोट पड रही है वह खतरा बढ जायेगा। पी० एल०—480 की बात हमारे सामने आयेगी। इस आग्रह के साथ मैं चाहता हू मंत्री महोदय गोल जवाब न दें, स्पष्ट जवाब दें कि इन तीन योजनाओं को चौथी योजना में निश्चित रूप से पूरा करेंगे, सारा पैसा उपलब्ध करायेंगे, राज्य सरकार मांगे या न मांगे क्योंकि कितना खर्चा होगा उसका हिसाब रखा है। और आप एक इंडेपेन्डेन्ट एथारिटी कायम करेंगे, केन्द्र का सुपरविजन वहा रहेगा और इस तरह से आप इनको पूरा करके रहेंगे। इस आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हू।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, राजस्थान के लिए राजस्थान कैनाल एक वरदान है। मैं आपसे पूछना चाहता हू कि आप स कैनाल को अगली पंचवर्षीय योजना में पूरा कर देंगे या उसमें भी कोई और रुकावट पैदा होगी और हम केवल एक स्वप्न देखते रहेंगे कि वह कब पूरी होती है।

दूसरे अभी जो सवाल हमारे सामने है क्या पोंग डैम के सम्बन्ध में आपको कैबिनेट का निर्णय मालूम है कि सारी पांचों टनेल बन्द होनी चाहिए क्योंकि उससे जो पानी मिलेगा वह राजस्थान में 12 महीने कैनाल में पानी बहेगा लेकिन ऐसा निर्णय होने के बाद भी उसका इम्प्लीमेन्टेशन नही हुआ जिसकी वजह से हमको पानी मिलेगा नही, हम खेती करने से महरूम हो जायेंगे। 10 लाख एकड जमीन सिंचित नही हो पायेगी। तो जो निर्णय लिया गया था क्या उसके पीछे आप जा रहे है यह सवाल है।

तीसरे मैं जानना चाहता हू कि शुरूआत में राजस्थान कैनाल की कुल कितने धन राशि की योजना थी और आज उसको पूरा करने में कितना पैसा लगेगा और क्या उतनी धनराशि आप अगली योजना में उपलब्ध करेंगे और उस काम को पूरा करवायेंगे—यह बतायें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, पश्चिम कोसी राजस्थान और गण्डक नहर योजनाओं को केन्द्रीय सरकार के हाथ में लेने की मांग बार-बार इस सदन में उठाई गई है तो इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हू कि सरकार इस सुझाव को मानने के लिए तैयार क्यों नही है और उसके सामने कौन सी कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से वह ऐसा नही कर सकती है? अगर सचमुच में सरकार ऐसा कर ले तो हमारे देश के बहुत बडे हिस्से में जो अनाज की कमी है वह पूरी हो सकती है। तो केन्द्रीय सरकार को उन्हें अपने हाथ में लेने में कौन सी कठि-नाई है?

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : सभापति जी, गण्डक योजना जिसमे 35 लाख एकड़ की सिंचाई होगी, नैपाल से इसका सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश से सम्बन्ध है, बिहार से सम्बन्ध है, तीन स्टेट्स से सम्बन्ध है और इसमे अब तक 1 अरब 30 करोड रुपया खर्च हो चुका है और इनके हिसाब से केवल 3 लाख एकड मे सिचाई हुई है। आप कह सकते है इतना रुपया कहां तक दें, उससे इन्फ्लेशन होगा और वह बात हम समझ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि नैपाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से इसका सम्बन्ध है और इसका एग्जीक्यूशन केवल नैपाल मे होता है और हमारी तरफ से यू०पी० गवर्नमेन्ट कुछ करती है लेकिन कसालिडेटेड काम नही होता है। अगर इसके निर्माण की जल्दी से व्यवस्था की जाये तो 35 लाख एकड मे सिचाई करने मे सारे देश मे फूड प्राब्लम बहुत हद तक हल हो सकती है। पता नही केन्द्रीय सरकार क्यो अपने हाथ मे इसको नही लेती है जबकि कटरापारा गुजरात मे है और बगाल की योजना का नाम मै भूल रहा हू—यह दो स्कीमे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने बना के उन स्टेट्स को दे दी। एक बार फखरुद्दीन साहब जब इसके मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि इसको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ले लेगी लेकिन आप जानते हैं हमारे आपस मे राजनीति चलती है, मोरारजी भाई ने कहा कि नही लेंगे। इसलिए मैं चाहता हू धर साहब वहा चलकर देखें, वे प्लानिंग के सुयोग्य मंत्री है। मैं कहना हू कि जल्दी से जल्दी हिन्दुस्तान की फूड प्राब्लम साल्व होगी अगर गण्डक योजना को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ मे ले ले और लेकर जल्दी से जल्दी बना दे। अगर केन्द्रीय सरकार इसको नहीं बनाती है तो यह बहुत दिनो तक चलती रहेगी, 12 साल तो हो गये और अभी नही मालूम और कितने साल लग जायेंगे तथा जितना पैसा लगता है उसका रिटर्न निकलता नही है।

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) : पश्चिम कोसी नहर एक बहुत बड़ी योजना है, इसकी स्वीकृति मे ही बहुत टाल मटोल हुयी। अब जब स्वीकृति हो गयी है तो कार्यान्वयन में टाल मटोल की नीति का सहारा लिया जा रहा है। केवल नैपाल की सीमा में काम प्रारम्भ हुआ है और वहां भी काम के मार्ग में अनेक बाधाएं हो रही हैं, या उपस्थित की जा रही हैं यह स्पष्ट नही है और हिन्दुस्तान की सीमा में इसकी चर्चा भी नहीं है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हू भारत की सीमा में कब से काम होने जा रहा है।

दूसरे इस काम को केन्द्रीय सरकार के द्वारा कराये जाने के मार्ग मे क्या कठिनाइयां हैं?

तीसरी बात यह है कि बिहार सरकार ने लिखित रूप मे अपनी असमर्थता व्यक्त की है और केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि यह कार्य केन्द्रीय सरकार के द्वारा ही हो और यहा बिहार के जितने एम० पीज० हैं, किसी भी पार्टी के, उन सबो का यह आग्रह है तो मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूगा कि वे इसकी स्वीकृति दे जिससे यह काम ठीक और उचित समय पर हो सके।

श्री लालजी भाई (उदयपुर) : पूरा राजस्थान अकाल से पीड़ित रहता है, और इस समय भी है, मैं जानना चाहता हू कि राजस्थान नहर कब तक पूरी हो जायेगी जिस से हम लोगों को राहत मिले, और वहा पर कितनी धनराशि खर्च होगी तथा कौन सी अवधि तक वह पूर्ण हो पायेगी। यह मैं जानना चाहता।

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI D. P. DHAR): Sir, I fully share the concern and the anxiety of hon. Members with regard to the progress of these three important projects, and I also share their wish that the Central Government and the State Governments in concert should do their best to accelerate the completion of these projects for the common good of the country and essentially for increasing food production. While this objective is unexceptionable, some of the difficulties, if I may say so with your permission, may kindly be borne in mind.

As far as Kosi is cencerned, it is not one project. It, in a sense, consists or comprises of two projects—the Kosi Canal and the Western Canal. An hon. Member has just asked me a question as to whether we have been able to clear that part of the Western Kosi project with Nepal which concerned that country. This in itself is an explanation of the delay that has been caused in this particular part of the Canal. It is only last year that we have come to an understanding with His Majesty's Government of Nepal with regard to the acquisition of the required land, over 34 km in Nepal territory. We have acquired land to the extent of 33 km. so far, not a bad job in a year, and work within the Nepalese territory is proceeding full speed ahead. Unless and until we are able to complete the headworks for this Canal which will lie in the Nepalese territory, it would not be feasible to proceed on an extensive basis with the work of the extension of this Canal within Bihar.

I am grateful to the hon. Member for having made some archaeological studies about the various stones and foundations which have been laid for the Canal. I would have been grateful, at the same time, if he had kindly cared to take into account some of the difficulties which were inherent in this project.

SHRI BHOGENDRA JHA: I do not agree that the Government of Nepal was to blame in this case. I have stated in this House earlier that the delay was on our side.

SHRI D. P. DHAR: I am sorry, Sir, that it was not an invitation to the hon. Member to blame an independent, sovereign country, Nepal. It is always our luck, or ill luck, to invite all the criticism and blame on ourselves. Therefore, the hon. Member need not use his knowledge to instruct me as to the causes of the delay for this Canal. I was only submitting some facts which were raised about which some enquiry was made by my hon. friend here

As far as the Gantak Canal is concerned, I would submit that this is one of the finest projects we have conceived in our country. It is capable of irrigating in its final phase nearly 1,100 thousand odd hectares of land in Bihar. The picture which Shri Bibhuti Mishra has drawn about the slow pace of the development of this Canal, more or less, corresponds to facts. These facts are unfortunate and these facts deserve to be remedied quickly. What steps we propose to take in that regard I will presently come to them.

The Rajasthan Canal, like Kosi Canal, is also a two-stage project. It is not in that respect one project. It is a two-stage project though it carries the same label, the same name, namely, the Rajasthan Canal. We have to, therefore, deal more effectively, more expeditiously, with the second stage of this project.

Before I proceed to answer one by one the questions which have been raised regarding the financial outlays in the Fifth Plan, regarding the provision of autonomous boards in regard to ensuring the technical and administrative guarantees for the completion of projects, before I come to detailed examination of these questions, I would submit for the information of the hon. Members that, in the first instance, the Fifth Plan is yet to be prepared. It would be slightly irresponsible of me if I anticipate in exact terms the quantum of money that will be available for these projects. I can made a broad guess and I am prepared to share that guess with the hon. Members. I hope, the hon. Member from Bihar Shri Bhogendra Jha, will not later on hold me to having indulged in a speculative exercise which I am doing purely for his satisfaction.

SHRI BHOGENDRA JHA: Only for implementation.

SHRI D. P. DHAR: My greater satisfaction will be to satisfy him by implementing these projects. If the implemen-

[Shri D. P. Dhar]

tation of these projects does not satisfy the hon. Member, I do not know what else will do.

In any case. I would submit, as far as Kosi and Gandak projects are concerned, I feel fairly confident that, by and large, appropriate financial outlays will be available for the Kosi Project and fairly appropriate outlays will be available for Western Kosi Canal in Bihar. I feel equally confident about the Gandak Project. About the Rajasthan Canal, State I, I am equally confident that the required amount will be available in the Fifth Plan period. We have only to examine the question of making the necessary financial outlays possible for the Rajasthan Canal, Stage II. This amount, according to our estimates, will be of the order of Rs. 89.12 crores. So far, in the Fourth Plan, it is our estimate that not more than Rs. 2-1/2 crores to Rs. 3 crores will be spent on this. Therefore, I am not sure that the entire balance amount of Rs. 86 crores will be available for the completion, in all respects, of the Rajasthan Canal, Stage II at this point of time. But taking into account the importance of this Canal, taking into account the benefits which are likely to accrue from this Canal and also, taking into account the fact that the Canal passes through one of the most arid and one of the most dry zones of our country, I think, the Planning Commission will do its utmost to see that this Canal is not stalled for want of finance and we will do our utmost to ensure its completion in the Fifth Plan period. Here it has been suggested that we should have autonomous boards. I would submit for my very learned and knowledgeable friend, Mr. Jha, the fact that there are boards at present which are functioning. For example, for Gandak, there is a Board under the chairmanship of the Governor of Bihar. For Kosi, there is a Board functioning under the chairmanship of the Chief Minister. Of course, it has been unfortunate that, for some years, we have had a spate of Chief Ministers in Bihar. That has somewhat disturbed the continuity of the process of development......

18 hrs.

SHRI BHOGENDRA JHA: Did the Chief Ministers know of this fact that they were the Chairman of the Board? At least does the present Chief Minister know that?

SHRI D. P. DHAR: Mr. Jha's Party was a party to these frequent changes. I mention this merely to draw on the knowledgeability of facts which Mr. Jha claims with regard to this particular project.

As far as Rajasthan Canal is concerned, there is a Committee of Directors under the chairmanship of the Central Minister for Irrigation and Power and the Chief Minister happens to be a member......

SHRI BHOGENDRA JHA: Are these autonomous Boards?

SHRI D. P. DHAR: I am slow in explaining my facts. I would be very greatful if the hon. Member could bear with me. Perhaps he might find some satisfaction in the submissions I am about to make.

I have said that it is not a fact that there are no Boards, that there are no directive authorities, that there are no organisations which are in charge of these projects. There are Boards. But what is the difficulty? The difficulty is that these Boards have so far, as the Estimates Committee have at one stage pointed out, concentrated on the completion of the engineering part of the project. The concurrent need to develop the areas with the help of the potential created by these projects has not been either felt or appropriately satisfied. Therefore, we have come to the conclusion, along with the hon. Member, that what we need is a different type of organisation, an organisation which is multi-disciplined in character, which has various disciplines connected with agricultural production in its composition. And when we talk of such a Board, when we talk of autonomy—I think it is a much-abused word, at any rate an ever-used word—, when we talk of a Board

which is multi-disciplined in character, we also want that it should be invested with sufficient powers more or less of the Government of the State, to deal with the problems as they arise and to deal with all the questions which are related to the speedy execution of the project. For this, we are in correspondence with the States, and I have been assured by all the three States concerned—by Uttar Pradesh, Bihar and Rajasthan—that Boards of this character would be set up......

SHRI BHOGENDRA JHA: By what time?

SHRI D. P. DHAR: Fairly soon.

The third question is whether the Centre would take over these—this was what was said before and what has been asked once again.

I need not remind hon Members that...

श्री लालजी भाई : हर योजना के लिये एक अवधि रखी जाती है। राजस्थान नहर के लिए क्या अवधि रखी गई है ?

SHRI D. P. DHAR: Irrigation is a State subject. Therefore, it is not enough declaring a wish that such and such project should be taken over by the Centre or it can automatically take it over etc.

श्री विभूति मिश्र : सभापति महोदय

SHRI D. P. DHAR: I am prepared to answer a supplementary question.

श्री विभूति मिश्र : सभापति महोदय, गण्डक का सम्बन्ध नेपाल से है। आधा बैराज नैपाल मे पड़ता है और आधा हिन्दुस्तान मे पड़ता है। अगर गंडक योजना को सैंटर ले ले तो नैपाल से पत्राचार और डीलिंग्ज मे सहूलियत होगी। आज स्थिति यह है कि बिहार गवर्नमेंट यहा चिट्ठी लिखती है और वह यहा से नैपाल जाती है और नैपाल से यहा जवाब आता है और वह बिहार गवर्नमेंट को भेजा जाता है। यद्यपि इर्रिगेशन एक स्टेट सबजेक्ट लेकिन सारा रुपया सैंट्रल गवर्नमेंट का लगता है, इस लिए वह इस योजना को ले ले।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध मे विभिन्न राज्य सरकारो से सलाह-मशवरा किया है? तभी पता चलेगा कि वे लोग इस के लिए तैयार है या नही और इस से क्या कठिनाई है।

श्री डी०पी० धर : आनरेबल मेम्बर और श्री मिश्र की ख्वाहिश का मुझे इज्जत है, लेकिन उस को पूरा करने के तरीके होते है और वे तरीके ऐसे नही हो सकते, जो आईन के खिलाफ हो। आईन मे यह बात साफ है कि सिंचाई का सबजेक्ट स्टेट्स के अख्त्यार मे है। अगर वह सबजेक्ट हम ने उन से हासिल करना है, या उस सबजेक्ट पर लेजिस्लेट करना है, या उस के सिलसिले मे किसी तरीके से बराहे-रास्त काम करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ आईनी कदम उठाये जाये। मैंने कहा है कि मुझे आनरेबल मेम्बर्ज की इस ख्वाहिश का एहतराम है, लेकिन एहतराम काफी नही है। एहतराम के सामने आईन की कुछ रुकावटें हैं और उन रुकावटो को हम ने दूर करना है। साफ और दियानतदारी की बात यह है कि जहा तक मेरा ताल्लुक है, मै अभी इस नतीजे पर नही पहुचा हू कि हमारी रियासती सरकारे इस काबिल नही है कि वे इन प्राजेक्ट्स को मुकम्मल कर सके। लेकिन अब मेरे मोहतरिम दोस्त और इस ऐवान के मेम्बर यह समझते हैं कि इन प्राजेक्ट्स मे ताखीर हो रही है, इस मे बहुत वक्त लग रहा है, इस लिए मरकजी हुकूमत को इन्हे अपने हाथ मे ले लेना चाहिए, तो मैं उन से अर्ज करूगा कि अगर ऐसे हालात हमारे सामने आये और हम इस बात पर मुतमईन हुए कि इन प्राजेक्ट्स की तकमील स्टेट सरकारो के बस का रोग नही है, तो जाहिर है कि ऐसे बड़े प्राजेक्ट्स के मुताल्लिक मरकजी

[श्री डी० पी० धर]
सरकार कुछ न कुछ मुनासिब कदम जरूर उठायेगी ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : बिहार सरकार ने यह रिक्वेस्ट की है कि वेस्टर्न कोसी कैनाल का एक्सीक्यूशन सैंट्रल गवर्नमैंट अपने हाथ मे ले ले ।

श्री डी० पी० धर : यह रिक्वेस्ट आते आते वक्त लगता है । अभी वह हमारे पास नही पहुची है । मुझे आनरेबल मेम्बर्ज की वकालत पर शुबहा नही है, लेकिन अगर कोई खत-पत्र उन की तरफ से आए, तो अच्छा हो ।

श्री भोगेन्द्र झा : वे आप के पास रिक्वेस्ट नही भेजेगे ।

श्री डी० पी० धर : यह फैसला आपस मे कर लीजिए । अगर आप मुझ पर एतबार करते हैं, तो मुझ पर छोड दीजिए ।

जहा तक इन तीनो प्राजेक्टस का ताल्लुक है, झा साहब ने कई बातो का तजकिरा किया है । जाहिर है कि कोसी, गडक और राजस्थान कैनाल मे से कुछ न कुछ सियासत निकालना मकसूद होता है । उन्होंने कुछ सियासत इस मे झाड दी— कुछ धतूरे की और कुछ दूसरी बातो की । लेकिन मैं उन बातो मे उलझना नही चाहता । क्योंकि उन बातो का कोई खास ताल्लुक हमारी बहस के साथ नही है । इसलिए मै आप की खिदमत मे सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हू कि ये तीन प्रोजेक्ट्स और यही तीन प्रोजेक्ट नही, बल्कि सारे देश मे हम ने कोई बीस एक प्रोजेक्ट्स ऐसे चुन लिए हैं जिन को हम नेशनल प्रोजेक्ट कहते हैं । नेशनल प्रोजेक्ट इस वजह से कहते हैं कि कौमी हैसियत मैं उन की एक खास अहमियत है और उन प्रोजेक्ट्स में इस तरह के फवायद हासिल करने की गुंजाइशें हैं जिससे कि हमारे अनाज की जो पैदावार है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और गडक, कोसी और राजस्थान इस सिलसिले मे एक इम्तियाजी हिस्सा रखते हैं । इस सिलसिले में इन बीस प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि सारे हिन्दुस्तान में फैले हुए है चाहे वह वेस्ट बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे उडीसा हो और चाहे हमारे दक्षिण के राज्य हो, वहा भी इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, और हमने इसीलिए इस बात का फैसला किया है कि मौजूदा प्लान मे, चौथे पंच वर्षीय प्लान के आखीरी साल मे जो, कि अब चल रहा है, हम इन पर ऐडवांस ऐक्शन लेने की बात सोच रहे है । उसके लिए पैसा भी रखा गया है बजट मे । आप इत्मीनान रखिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे और हम को पूरी कोशिश करनी चाहिए । इस मे मैं समझता हू कि झा साहब जरूर हम से गिले व शिकायतें करे लेकिन अब काम करने का वक्त आया है और उसमें वह हमारी मदद करें । हम आप के मशकूर है ।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

18.12 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, May 8 1973/Vaisakha 18 1895 (Saka).

MGIPRRND—13 LSS/73—Sec. II (N.S)—31-8-73—1010.